

न्यायिक जवाबदेही और के. वीरास्वामी नरिणय, 1991

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

उपराष्ट्रपति ने [आंतरिक जाँच/इन-हाउस इनक्वायरी](#) के संवैधानिक आधार को चुनौती दी और न्यायमूर्त विरमा के आवास पर नकदी जब्त होने के बाद [के. वीरास्वामी नरिणय, 1991](#) की समीक्षा की मांग की, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्त विरमा के खिलाफ [FIR](#) याचिकाओं को खारज कर दिया था तथा आंतरिक जाँच जारी रखने की अनुमति दी थी।

- **आंतरिक जाँच: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)** द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा आंतरिक जाँच की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किसी न्यायाधीश के खिलाफ **प्रथम दृष्टया मामला है या नहीं**।
 - दोषी न्यायाधीशों के संबंध में मुख्य न्यायाधीश की शक्तियाँ उन्हें सौंपे गए **कार्य को स्थानांतरित करने** या वापस लेने तथा संबंधित न्यायाधीश के खिलाफ **महाभियोग की सफारिश करने** तक सीमित हैं।
 - संवधान के तहत, [अनुच्छेद 124](#) के तहत महाभियोग एकमात्र संवैधानिक निकासन प्रक्रिया है, लेकिन **75 वर्षों में यह कभी सफल नहीं हुई**।
 - वर्ष 2019 में तत्कालीन CJI रंजन गोगोई ने [CBI](#) को **जस्टिस एस. एन. शुक्ला** के खिलाफ FIR दर्ज करने की अनुमति दी थी, जबकि **CJI दीपक मशिरा ने महाभियोग** की सफारिश की थी जिसे सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया था।
- **के. वीरास्वामी नरिणय, 1991:** इसने न्यायाधीशों को **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम** के तहत लोक सेवकों के रूप में वर्गीकृत किया, लेकिन अभियोजन (FIR दर्ज करना) के लिये **मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी की आवश्यकता होती है**, जिससे न्यायपालिका को अंतर्निति प्रतिक्रिया के साथ कार्यपालिका के हस्तक्षेप से सुरक्षा मिलती है।
- **संवधान के तहत अनुमक्ति:** राष्ट्रपति और [राज्यपालों \(अनुच्छेद 361\)](#) के वपिरीत, संवधान के तहत **न्यायाधीशों को कोई अनुमक्ति नहीं है**।
 - उपराष्ट्रपति का तर्क है कि **अभियोजन की मंजूरी** उस प्राधिकारी से मिलनी चाहिये जो लोक सेवक को नियुक्त करता है, अर्थात् **भारत के राष्ट्रपति**, जिन्हें [अनुच्छेद 53](#) के तहत कार्यकारी शक्तियाँ प्राप्त हैं।

और पढ़ें: [न्यायिक स्थानांतरण और इन-हाउस इनक्वायरी](#)